मेहनतकशों का पैग़ाम
Email : mazdoormorcha@yahoo.co.in
मेहनतकशों के नाम

मज़दूर मोर्चा

पाक्षिक

नेट पर उपलब्ध :
www.mazdoormorcha.com

Postal Reg. No. L/H.R/FBD/463-06 /R.N.I. No. 66400/97

खुद अपाहिज है अस्पताल : कैसे ठीक कर सकते हैं ... बी के अस्पताल का लुटेरा पी एम ओ हटा 3
स्त्री हिंसा क्यों नहीं रुकेगी मोदी क्या–क्या बांटेगा: भाजपा तो बांट दी 4
आधार क्यों जरूरी है? महिलाओं के वस्त्र और यौन हिंसा 6
पार्षद गोसाईं को गुस्सा क्यों आया बरसात चली गयी, सड़कें बह गयी 8

वर्ष 26 अंक 21 फरीदाबाद, सोमवार, 16-30 सितंबर 2013 फोन : - 9999595632 सहयोग राशि 2 रुपया

बालश्रमिक की हत्या पर सन्नाटा

श्रम विभाग तो जागा पुलिस जागने को तैयार नहीं

बल्लबगढ (म.मो.) के एल जे ग्रुप के लिये फ्लैटों का निर्माण करने वाली कम्पनी जी डी बिल्डर्स की आपराधिक लापरवाही के चलते 7 सितम्बर को सायं 4 बजे के करीब एक 13 वर्षीय बाल-श्रमिक की मौत हो गयी। नकीबुल हसन नामक इस श्रमिक को बिल्डर कम्पनी ने (मंकी) लिफ्ट आप्रेटर के तौर पर रखा हुआ था। यह लिफ्ट 18 मंजिले टावर पर सीमेंट, रोड़ी, पत्थर आदि पहुंचाने में प्रयुक्त की जाती है। जनरेटर की बिजली से चलने वाली इस लिफ्ट में ए सी के बजाय डी सी करंट का इस्तेमाल किया जाता है।

सुरक्षा नियमों के अनुसार किसी भी बिजली उपकरण को एम सी बी अथवा फ्यूज कट-आउट के बगैर नहीं चलाया जाना चाहिए। इनका प्रयोग इसलिए किया जाता है कि दुर्घटना होने या किसी को करंट लग जाने पर बिजली का प्रवाह तुरन्त रूक जाय। 'मज़दूर मोर्चा' द्वारा की गयी जांच-पड़ताल में पाया गया कि इस लिफ्ट में उक्त सुरक्षा उपकरणों जैसा कुछ भी नहीं लगा था। इस कमी के चलते 18 वी मंजिल पर बिजली ने नकी को ऐसा पकड़ा कि उसका शरीर जलने लगा; जलने से उठने वाले धुए को नीचे खड़े लोग़ों ने जब देखा तो उन्होंने तुरंत जनरेटर बंद किया और भाग कर ऊपर गये, तब तक नकी जल कर मर चुका था।

कई जानकारों के अनुसार लिफ्ट में उक्त सुरक्षा उपकरण लगाने से जरा भी

न किसी ने संज्ञान लिया न कोई लेना चाहता है

ओवरलोड होने या कोई छोटी-मोटी बात होने पर लिफ्ट बार-बार ट्रिप होगी जिससे काम रूक जायेगा और जान-माल का नुकसान बच जायेगा। बिना रुके, अनाप-शनाप ढंग से काम चलाने के लिये इस तरह की लिफ्टों को सुरक्षा उपकरणों से मुक्त रखा जाता है। कोई मरता है तो मरे, उनकी बला से, नकी जैसे मज़दूरों की कोई कमी थोड़े ही है, एक मरेगा तो दस काम मांगने आयेंगे।

नकी की मृत्यु के पश्चात, नियमानुसार पुलिस को सूचित करने, पोस्ट मार्टम कराने आदि की तमाम कानूनी औपचारिकताओं को दरकिनार करते हुए बिल्डर कम्पनी ने अगले ही दिन, दिनांक 8 सितम्बर को उसके शरीर को चुप-चाप बल्लबगढ मुख्य बस अड्डे कि निकट बने कब्रिस्तान में दफ़न कर दिया। ऐसा करके कम्पनी ने अपनी अपराधिक कारगुजारी का मुख्य सबूत ही नष्ट कर दिया। अब भी बिल्डर ने लिफ्ट मशीन की खामियां दूर करते हुए वांछित सुरक्षा-उपकरण लगाने की जरूरत नहीं महसूस की है। नकी का कच्चा सर्विस रिकार्ड यानी वह कब काम पर लगा था, उसकी आयु क्या थी, उसका वेतन कितना था आदि-आदि सब खुर्द-बुर्द कर दिये गयें हैं। 8 तारीख को जब इस संवाददाता ने बल्लबगढ़ के ए सी पी दिनेश यादव से फ़ोन कर इस बाबत की गयी पुलिस कार्यवाही के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि उन्हें इस मामले की कोई जानकारी नहीं है क्योंकि यह थाना सदर का केस है जो डी सी पी सुखबीर सिंह की निगरानी में है; फ़िर भी वे एस एच ओ व डी सी पी से इस बाबत बात करेंगे। तीन दिन पश्चात इस बाबत जब डी सी पी से जानना चाहा तो उन्होंने बताया कि वे तो तीन दिन से दिल्ली में किसी कोर्स पर हैं, इसलिये उन्हें नहीं पता कि क्या मामला है क्या नहीं। इस बाबत पुलिस कमिश्नर से सम्पर्क करने का प्रयास किया गया जो सफ़ल नहीं हो सका।

कानून की दृष्टि से देखा जाय तो कम्पनी का पहला गुनाह बाल-श्रमिक को काम पर लगाना है। दूसरा गुनाह अपना काम ज्यादा गति से निकालने के लालच में सुरक्षा की अनदेखी करते हुए बाल-श्रमिक को मौत के मुंह में धकेलना है जो भारतीय दंड संहिता की धारा 304 के अर्न्तगत आता है, तीसरा पुलिस को रिपोर्ट न करके शव दफ़ना कर सबूत को खुर्द बुर्द करना भरतीय दंड संहिता की धारा 201 के तहत आता है। लेकिन ये धारायें तो मज़दूर के हत्यारों पर तब लगेंगी न जब पुलिस कुछ कार्यवाही करेगी, कानून हरकत में आयेगा।

शेष पेज 2 पर

फुकरापंथी का मारा एक डीजीपी बेचारा

डीजीपी रंजीव सिंह दलाल : वक्त चला गया

झज्जर (विशेष संवाददाता) 6 साल तक हरियाणा के डीजीपी रहे रंजीव सिंह दलाल गत वर्ष अक्तूबर में सेवानिवृत हो गये थे। लेकिन अभी भी जनता, खासकर अपने गांव के लोग़ों को अपनी अफ़सरी शान दिखाने की ललक उनकी पूरी नहीं हुई। इसी झूठी शान को बघारने की लालसा में रंजीव दलाल ने एसपी झज्जर विकास धनखड़ को फ़ोन लगाकर कहा कि उन्हें अपने गांव डाबोधा जाना है। इसके लिये वह एक जिप्सी बतौर पायलेट और एक जिप्सी बतौर एस्कार्ट उन्हें मुहैय्या कराए।

धनखड़ ने बड़ी चतुराई से उन्हें समझाने का प्रयास किया कि गांव के लोग बड़े ऊत व खुंदकी होते हैं, और आपके गांव के तो खासतौर पर; कहीं वे आपका अपमान न कर दें लाव-लश्कर देख कर, क्योंकि इससे पहले (जब आप अफ़सरी में थे) तो कभी गांव जाते नहीं थे। इस पर दलाल ने बनाया कि वे दो बार गांव गये थे और गांव वालों ने उन्हें सम्मानित भी किया था। इस पर धनखड़ ने उन्हें पुन: समझाने का प्रयास किया कि चलो अच्छी बात है, उस समय गांव वालों ने आपको सम्मानित कर दिया, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि आप उनके लिये कुछ करेंगे जो अब नहीं रही। इसके अलावा ग्रामीणों ने यदि पायलेट व एस्कार्ट गाड़ियों या आपके साथ कोई छेड़खानी कर दी तो उसके लिये एक नई मुसीबत खड़ी हो जायेगी। वह किस-किस को जवाब देता फ़िरेगा। और यदि मीडिया में यह सब आ गया तो उसकी अपनी नौकरी खतरे में पड़ सकती है। इस पर दलाल साहब ने काफ़ी नाराज़ और मायूस हो कर कहा कि तूने गाड़ियां नहीं देनी तो मत दे लेक्चर तो मत दे।

शेष पेज 2 पर

लालू की याद दिला दी

उत्तर प्रदेश में मुजफ्फर नगर में हिन्दू-मुस्लिम दंगों को रोक पाने में असफल प्रदेश सरकार ने बिहार के लालू-दौर को बेहद प्रभावी प्रशासन सिद्ध कर दिया। लालू का दौर बिहार के लिऐ बदहाली, कुशासन और अपराधों का दौर था। इससे घटिया सरकार की कल्पना भी नहीं की जा सकती जिसका नारा ही 'विकास-विरोध' था। पर चुनावी गणित के चलते लालू ने एम वाई (मुस्लिम-यादव) समीकरण का वोट-बैंक बरकार रखने में एड़ी-चोटी लगा रखी थी। इसलिये सारे प्रशासन की चौकसी एवं विश्वसनीयता की एकमात्र शर्त होती थी कि प्रदेश में कहीं भी साम्प्रदायिक दंगे न होने पायें। यहां तक कि 1992 में बाबरी मस्जिद कांड से पहले आडवाणी की आग लगाऊ रथ यात्रा और मस्जिद टूटने के बाद के दंगों के देशव्यापी दौर में भी बिहार का साम्प्रदायिक वातावरण पूरी तरह स्वच्छ रखा गया था। मुजफ़्फरनगर के दंगों में मुलायम-अखिलेश की नाकारापंथी और मनमोहन की केन्द्रीय सरकार की कुंभकरणी निद्रा ने लालू की याद दिला दी। ■

ख़बर दार

मुज़फ़्फ़रनगर, मोदी, मुलायम सत्ता का खेल कायम

मुलायम और लालू दोनों की राजनीतिक ज़मीन मुस्लिम वोटों के सहारे आबाद रही है। हालांकि दोनों का नज़रिया एक ही रहा है कि कैसे ये वोट किसी और की झोली में न जा गिरें, पर यह हासिल करने के लिये उनके तरीकों में बुनियादी फ़र्क रहा है। लालू ने बिहार में मुसलमानों को साम्प्रदायिक दंगों की चपेट से बचा कर वोट हासिल किये। जबकि यूपी में मुलायम ने मुसलमानों को भाजपा का डर दिखा वोट हथियाये हैं।

क्योंकि लालू कुशासन के बादशाह और विकास के महाविरोधी थे, लिहाजा एक सीमा के बाद अपनी सुरक्षा को

लेकर कृतज्ञ होने के बावजूद मुसलमानों ने लालू का साथ अन्तत: छोड़ दिया। लालू न केवल सत्ता से बाहर हुए बल्कि अब उनके लिये वापसी कर पाना बीहड़ काम हो चुंका है।

यूपी में भी मुलायम पार्टी की गुंडागर्दी से उकताए मतदाताओं ने सन् 2007 में सपा की छुट्टी कर दी और पहली बार पूरी तरह मायावती की बसपा के आसरे गये । इस बीच लोकसभा के चुनाव 2009 में हुए। भाजपा से बचने के लिये और क्याकि मुलायम के कुशासन के प्रति उनकी चिढ़ बरकरार थी, मुसलमानों ने कांग्रेस को वोट दिया। सन् 2012 तक मायावती सरकार पूरी तरह अपनी विश्वसनीयता खो चुकी थी। यहां तक कि मायावती के भाजपा से हाथ मिलाने के स्वर भी सुनाई देने लगे थे। एक बार फ़िर मुसलमान वोट मुलायम के पाले में गये और यूपी में बेटे अखिलेश को गद्दी पर बैठाकर वे स्वयं प्रधानमंत्री की कुर्सी के हसीन सपने देखने लगे।

शेष पेज 2 पर

'काबिल' आर बी आई

गवर्नर की बेहतर कार्पोरेट सेवा

बड़े कार्पोरेट के हित-साधन में लगी मनमोहन-चिदम्बरम-मोनटेक की सरकार ने नकारा सिद्ध हो रहे पुराने प्यादे सुब्बाराव की जगह आर बी आई गवर्नर की कुर्सी पर 'काबिल' रघुराम को बैठा दिया है। नये प्यादे के आगमन को कार्पोरेट मीडिया में खूब उछाला भी गया है। रघुराम का एकमात्र दायित्व फ़िलहाल रुपये को डॉलर के मुकाबले मजबूत करना है। इसी को लेकर वह मुनाफ़ाखोर निवेशकों को आश्वस्त करने वाले बयानों व कदमों की घोषणाओं में जुटा हुआ है। पेंशन फंड तक में खुले मुनाफ़े का माहौल बनता देख विदेशी निवेशक भी 'फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट' तथा शेयर मार्केट की प्रणाली से भारतीय बाज़ारों की ओर आने शुरू हो गये हैं। किस्मत से सीरिया पर अमेरिकी हमले का खतरा भी फ़िलहाल टल गया है

जिससे मध्य-पूर्व के तेल-बाज़ारों की संभावित उथल-पुथल पर लगाम लग गयी है। उधर अमेरिकी सरकार द्वारा प्रति माह 75 विलियन डालर अर्थव्यवस्था में डालने पर रोक की बात भी फिलहाल टल गयी है। साथ ही दो-तीन महीनों से चल रहे रुपये के जबरदस्त अवमूल्यन ने भारतीय निर्यात में भी जान फूंकनी शुरू कर दी है। इन सब का मिला-जुला परिणाम रुपया की मजबूती में नज़र आता है। यानी बड़े कार्पोरेट को सस्ते डॉलर पहुंचाने का काम काबिल प्यादे रघुराम ने संभाल लिया है। देश की जनता जाय भाड़ में।